कोई धन देने का विचार है ? वर्ल्ड बैंक की लिस्ट में भी यह योजना नहीं है ।

श्री राम निवास मिर्धा : श्रीमन् यह प्रश्न भी इससे नहीं उठता है । फिर भी माननीय सदस्या अगर चाहती है तो मैं इसका उत्तर दे देता हूं ।

जिस योजना का माननीय सदस्या उल्लेख कर रही हैं, इसका पहले भी कई दफा जिक्र हो चुका है । राज्य सरकार यह योजना बना रही है । कुछ योजना उन्होंने क्रियान्वित भी की है । इसके सम्बन्ध में विशेष सहायता देने का प्रश्न नहीं उठता है । राज्य सरकार स्वयं अपने साधन से उसको बनायेगी ।

श्री दिलीप सिंह भूरिया : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश की माही परियोजना है जिस पर मध्य प्रदेश सरकार का तीन करोड़ रुपया खर्च हो चुका है । स्टाफ के बहुत सारे क्वार्टर बना दिये गये हैं, सड़कें बना दी गयी हैं । तीन करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी वह स्कीम अधर में लटकी हुई है । वहां स्टाफ लगा हुआ है, इंजीनियर काम कर रहे हैं और बैठे-बैठे वेतन और पैसा ले रहे हैं । क्या वर्ल्ड बैंक उसके लिए पैसा देगा या नहीं देगा । जब यह सारा का सारा पैसा वहां खर्च हो रहा है तो ऐसी स्थिति में अगर वर्ल्ड बैंक पैसा नहीं देता है तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट को पैसा देना चाहिये क्योंकि यह योजना पिछड़े क्षेत्र में है और आदिवासियों की जमीन पर वह योजना बन रही है । अगर उसके लिए वर्ल्ड बैंक पैसा नहीं देगा तो क्या सेन्ट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी, यह मैं जानना चाहता हूं ।

श्री राम निवास मिर्धा : राज्य सरकारें योजनाएं अपने स्वयं के साधनों से प्रारंभ कर लेती हैं, उनका सर्वेक्षण प्रारम्भ कर लेती हैं । क्योंकि योजनाएं हैं, बड़ी-बड़ी योजनाए हैं और उसकी वजह से काफी सर्वेक्षण करना पड़ता है और इसके बाद ही योजना तैयार हो सकती है । इसलिए अगर 2-3 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके बारे में कोई एतराज किया जाए । और जहां तक वर्ल्ड बैंक सहायता का सवाल है, अभी तक माही के संबंध में कोई योजना हमारे पास नहीं आई जो वर्ल्ड बैंक को भेजी जाए ।

Financial assistance to Indian construction companies

*205. SHRI DHARAM DASS SHASTRI :
SHRI K. LAKKAPPA :

Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) whether some Indian construction companies are not able to complete projects undertaken in Iraq, Iran. Libya and some other Gulf countries for lack of finances; if so, full facts in this regard;

(b) whether the construction companies in questions have approached the Government for financial assistance to complete their contracted projects;

(c) if so, the particulars thereof and the projects undertaken by them and action taken by Government to provide them financial assistance so far; and

(d) whether Government have also enquired into the reports appearing in the press that the management of these companies are misusing the funds, perscuting the labour etc., and if so, action taken against them?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF SPORTS, IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUS-

ING AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : (a) This Ministry has no information about private construction companies working abroad. According to the information available with this Ministry, some of the projects of the following central govt. public sector construction companies have been delayed due to constraints of financies arising out at non-paymeat of due amounts from their clients abroad.

	No. of Projects delayed in	
	Iraq	Libya
1. N.B.C.C. (National Buildings Const. Corpon.)	4	15
2. Engg. Projects (India) Ltd.	2	—
3. International Airport Authority of India	—	2
4. National Projects Constn. Corpn.	1	—
5. Indian Road Constn. Corpn.	2	6

(b) No, Sir.

(c) Question does not arise.

(d) The companies referred to in (a) above have reported that there has been no misuse of funds or persecution of labour.

श्री धर्मदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, आप प्रजातंत्र के मंदिर के अध्यक्ष है । आप मंत्रियों का संरक्षण करें, हमें कोई एतराज नहीं है । लेकिन जो सदस्यों के अधिकार हैं, उन अधिकारों के मुताबिक मंत्री महोदय उत्तर ही न दें, यह कहां तक उचित है । इन्होंने अपनी कंपनियों के नाम सुना दिए लेकिन देश में इस तरह की कंपनियां हैं जैसे उत्तम सिंह उत्कल कंपनी, डी० एस० कांस्ट्रक्शन कंपनी, कांटीनेंटल कांस्ट्रक्शन कंपनी, ये मजदूरों का शोषण कर रही हैं । एक तरफ तो लेबर ला बना हुआ है और दूसरी तरफ मजदूर भूखे मर रहे हैं । मंत्री सिर्फ मंत्रालय का ही मंत्री नहीं होता, वह देश का मंत्री होता है । अगर कोई कंपनी कहीं भी जाकर मजदूरों का शोषण करती है तो इससे देश का नाम बदनाम होता है । इसलिए मंत्री महोदय राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न का उत्तर दें । अध्यक्ष महोदय, आप केवल मंत्रियों का ही संरक्षण मत करिए, सदस्यों का भी करिए ।

श्री मल्लिकार्जुन : इस देश में प्रजातंत्र अवश्य है और नागरिकों को हर तरह की स्वतंत्रता होने के कारण हर नागरिक अपने ढंग से काम कर रहा है । कुछ लोग किसी ढंग से कांट्रेक्ट्स ले लेते है और लेबर को

तकलीफ पहुंचाते हैं। लेबर के बारे में जो कठिनाइयां हैं उसके बारे में लेबर मंत्रालय बता सकता है। लीबिया और इराक में एन० बी० सी० सी० के प्रोजेक्ट्स हैं।

...(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वह लीबिया की बात नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पूछा है कि जो लेबर बाहर जाती है, उसका संरक्षण कौन करता है ? इस बात की जिम्मेदारी किसकी है ?

श्री मल्लिकार्जुन : जहां तक लेबर के हित का सवाल है, वह मेरा मंत्रालय डील नहीं करता। उसके लिए लेबर मंत्रालय अलग है।

श्री धर्मदास शास्त्री : मैं सदन के अंदर कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ रहे हैं। मैन-पावर सप्लाई करने वाली कंपनियों पर लेबर मिनिस्ट्री ने कानून बनाकर कंट्रोल किया है।

जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां दूसरे मुल्कों में काम लेती हैं, उन पर कंट्रोल नहीं हो सकता। इस तरह से मंत्री जी उत्तर देकर अपने उत्तरदायित्व से बचना चाहते हैं। यह पार्लियामेंट राष्ट्रीय मंच है और मंत्री चाहें कि शब्दों के हेर-फेर से हमें संतुष्ट कर लेंगे तो वह हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं।

श्री मल्लिकार्जुन : कौन समर्थ है और कौन असमर्थ है, यह अलग बात है। मैन-पावर के बारे में जैसा कि माननीय सदस्य बता रहे हैं, वह मेरे मंत्रालय से संबंधित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह लेबर मिनिस्ट्री को भेजना चाहिए था।

श्री धर्मदास शास्त्री : मंत्री जी को इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहिए था क्योंकि उन्हें यह भी मालूम नहीं कि यह प्रश्न उनके मंत्रालय से संबंध रखता है या नहीं ? सिर्फ ए भाग का उत्तर दिया है। लेकिन इसमें तो ए से लेकर डी तक है। यह तो ए, बी, सी, डी, की ही बात है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यहां तो सिर्फ चार अक्षर ही थे।

श्री मल्लिकार्जुन : बिना ए, बी, सी, डी, सीखे हुए, मैं यहां आया नहीं हूं। जहां तक लेबर की समस्या का सवाल है .....(व्यवधान)

MR. SPEAKER : Why cannot it be referred to the Labour Ministry?

SHRI K. LAKKAPPA : My friends has deliberately given for the Government run companies which are working in Iran, Iraq and Libya. For the other part he has not said anything.

MR. SPEAKER : For labour part, we can have a half-an-hour discussion.

SHRI K. LAKKAPPA : It is not Member's mistake The whole House knows that he has already answered the question. Now he is coming out with the plea that it relates to the Labour Ministry He has stated in part (d) that the companies referred to in (a) above have reported that there has been no misuse of or persecution of Labour. Now he wants to take a plea that he is going to refer it to the Labour Ministry but directly or indirectly he has also referred to the Labour.. How far is it relevant now to refer to the Labour Ministry? Now I would like to put a supplementary.

Mr. SPEAKER : You have me stunned.

SHRI K. LAKKAPPA : I want to know whether this Government..... (*Interruptions*) I am not yielding. The point is whether this Government has got any record of running private companies registered under the labour laws and working under the Housing Ministry for construction work abroad and if so, if the Minister has got any record, I would like to know whether M/s. Uttam Singh Duggal & Company; New Delhi, M/s. D. S. Construction Company, New Delhi and M/s. Continental Construction Company which have undertaken the construction contracts of a number of projects in India and abroad are holding labour like prisoners, depriving them of their wages, bringing them back to India only after the completion of the work and leaving them penniless to their fate. M/s. Uttam Singh Duggal & Company have undertaken the construction work of Baghdad University in Iraq which is lying incomplete and are holding the labour like prisoners there. Not only that, the labour has approached the Government for redressal of their financial difficulty. So, I would like to know from the Minister whether it is a fact and if so, to what extent they have misused, to what extent they have abused, to what extent they have cheated the labour, to what extent...(*Interruption*)

MR. SPEAKER : No more elaboration.

SHRI K. LAKKAPPA : I would like to know whether the company has got itself registered with this Ministry and if not, why enquiry has not been made by this Ministry?

MR. SPEAKER : I think the Ministry could have asked our Secretariat that this part of the question is not theirs and we could have referred it to the other Ministry in future...

(*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN : But in any case we will culminate the situation now and than they can put it to the Ministry of Labour.

MR. SPEAKER : I think we shall have Half-an-Hour discussion and both the Ministries, including the Labour Ministry, shall be present.

(*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN : Sir, the hon. Member has referred to a number of companies which have nothing to do with the Works and Housing Ministry. So for as the construction which has been undertaken by our public undertaking...(*Interruptions*).

SHRI K. LAKKAPPA : I have not put question on that I have never put question on that. I have not put the question regarding the working of the Government companies. You please go through the question again..... (*Interruptions*).

SHRI MALLIKARJUN : I am categorically crystal clear that the said construction companies referred to by the hon. Member have nothing to do with my Ministry.

MR. SPEAKER : I will allow that question to be taken up later on and will allow Half-an-Hour discussion on that. We will take it up for Half-an-Hour discussion.

National Body of Boost Oilseeds Production in Seventh Plan

\+

*208. SHRI M. RAMGOPAL REDDY :
SHRI SUBHASH YADAV :

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether there is any proposal under consideration of Government to set up a national body on oilseeds during the Seventh Plan period to boost production of oilseeds;